बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 59

तेल कीमतों पर `नियंत्रण'

ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क के आधार पर मापे जाने वाले कच्चे तेल का वैश्विक मूल्य ईरान पर पाबंदियां सख्त होने के बीच गुरुवार को वर्ष 2019 में पहली बार 75 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों की भावी राह अनिश्चित है लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि मध्यम अवधि में यह 80 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर भी जा सकता है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इस हफ्ते यह साफ कर दिया है कि भारत समेत आठ देशों को ईरान से तेल खरीदने के लिए दी गई छूट की मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी। ईरान समस्या के अलावा कच्चे तेल के निर्यात में कटौती करने के रूस के कदम ने भी वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को साल के सबसे ऊंचे स्तर पर ला दिया है। ईरान के तेल निर्यात पर लगी अमेरिकी पाबंदियों से मिली छूट भारत के लिए काफी लाभप्रद रही है लेकिन हालिया घटनाक्रम से वह निरापद नहीं रह सकता है। ऐसे में तार्किक ढंग से देखें तो भारत में पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले तेल के दाम भी इस उठापटक से प्रभावित होंगे। आखिरकार भारत में पेट्रोल एवं डीजल के दामों पर अब नियमन नहीं है और वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के हिसाब से ही तय होंगे। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जून 2017 से ही पखवाड़े के बजाय दैनिक आधार पर तय करने शुरू कर दिए हैं।

लेकिन पिछले छह हफ्तों में कच्चे तेल के एक बैरल का भाव वैश्विक बाजार में करीब 10 डॉलर तक बढ़ चुका है। मार्च की शुरुआत में कच्चा तेल 65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था लेकिन अब यह 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब जा पहुंचा है। ऐसे में एक नियमन-रहित बाजार में भारत के एक पंप पर पेट्रोल के भाव 10-15 फीसदी तक बढ़ गए होते। लेकिन आंशिक बढ़ोतरी के सिवाय घरेलू स्तर पर तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। यह चिंताजनक है। यह एक और संकेत है कि तेल कीमतों को विनियमित करने के दावों के बावजूद भारत में राजनीतिक चिंताएं तेल के दाम तय करने के समय और मात्रा को अब भी निर्धारित कर रही हैं। मौजूदा समय में आम चुनाव की प्रक्रिया जारी होने से इस धारणा को बल मिलता है कि राजनीति के चलते घरेलू तेल कंपनियां अपनी लागत बढ़ने के बावजूद तेल कीमतें नहीं बढ़ा पाई हैं। इस धारणा के समर्थन में ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। पिछले साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के समय भी वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल एवं डीजल के भाव नहीं बढ़ने दिए गए थे। ऐसा स्पष्ट नजर आता है कि तेल कीमतों को विनियमित करने की नीति को कमतर बनाया जा रहा है।

यह दूरदर्शी सोच नहीं है। तेल कीमतों के विनियमन के जरिये जनता को यह जताने की कोशिश की गई थी कि पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य भारत सरकार के नियंत्रण के बाहर जा चुके हैं। अगर भारत सरकार इन कीमतों पर काबू पाने की कोशिश करती है तो वह हद से ज्यादा खर्च करने और उसके चलते राजकोषीय घाटा बढ़ने की समस्या में फंस सकती है। ऐसा होने पर न केवल चालू खाते का घाटा बढ़ेगा बल्कि अर्थव्यवस्था के भी संकट में फंसने का जोखिम हो जाएगा। लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम तय करने में अब भी राजनीतिक कारकों की भूमिका होने का लोगों को संकेत देकर तेल मूल्य विनियमन से जुड़े सारे अच्छे कामों एवं दर्द को भुलाया जा रहा है। यही उम्मीद की जानी चाहिए कि तेल कंपनियां जब भी मूल्य पुनरीक्षण करें तो उन्हें अच्छी-खासी बढ़ोतरी करनी चाहिए, चाहे चुनाव पूरे न हुए हों। ऐसा नहीं होने पर गंदी राजनीति के चलते बनी-बनाई विश्वसनीयता गंवा दी जाएगी।

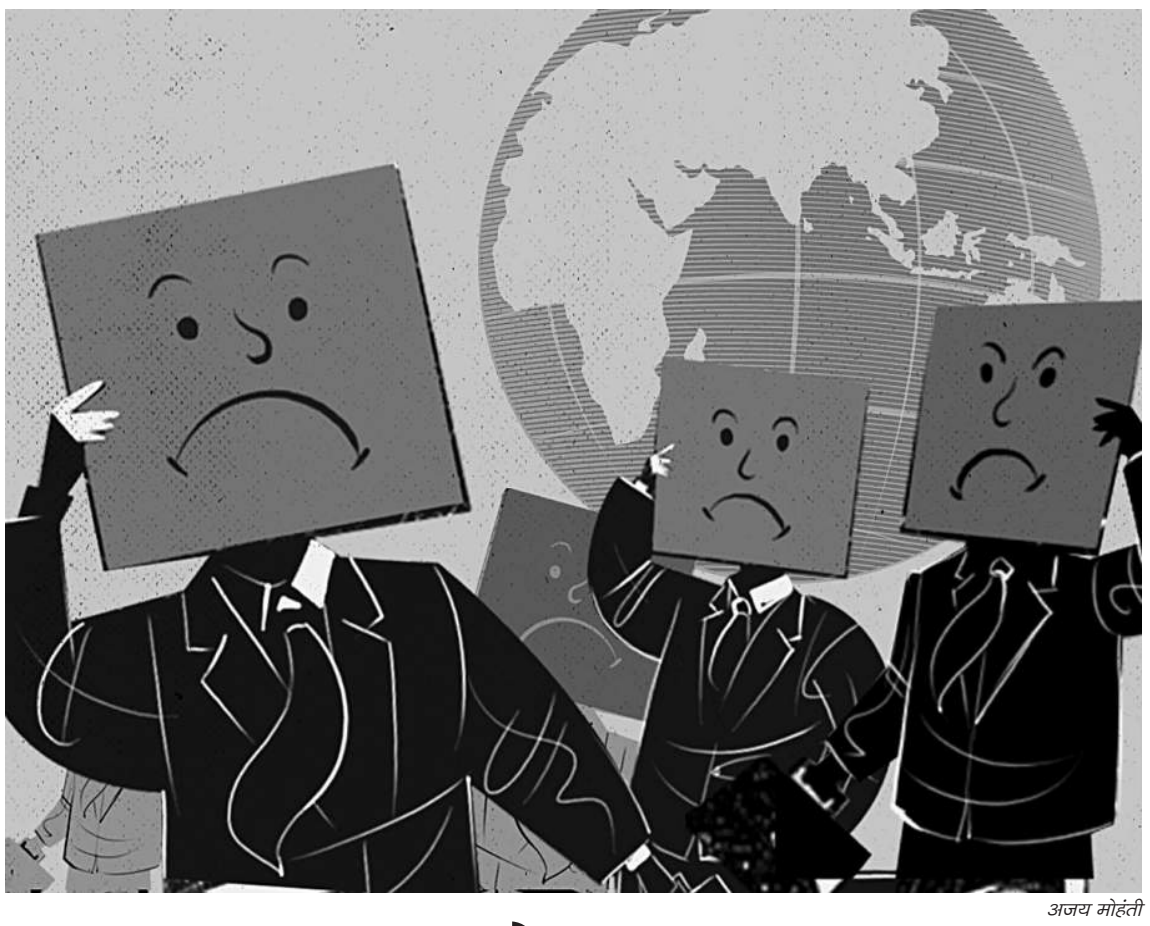

अजय मोहंती

खुशी के पैमाने पर काफी पीछे भारतीय

वैश्विक स्तर पर तुलना की जाए तो भारतीय समाज अत्यंत नाखुश है और उसकी नाखुशी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं पार्थसारथि शोम

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 के लिए खुशहाली की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक भारत में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे अधिक अप्रसन्न लोगों में शुमार किए गए हैं। इतना ही नहीं हाल के कुछ वर्षों में भारत के लोगों की नाखुशी में लगातार इजाफा देखने को मिला है।

इससे पहले हम देख चुके हैं कि गरीबी और आय के वितरण के मामले में हमारा रिकॉर्ड कितना खराब रहा है। अतीत में इन विषयों पर मैंने इस समाचार पत्र में कई आलेख लिखे हैं। दुख की बात यह है कि हम भारतीय सामाजिक और पारिवारिक समर्थन जैसी जिन बातों पर बहुत अधिक भरोसा करते आए हैं, उन मोर्चों पर भी खुशहाली के सूचकांक पर हमारा प्रदर्शन कमजोर ही साबित हुआ है। रिपोर्ट का आकार बहुत बड़ा है और इसका बहुत बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक है।

रिपोर्ट में 156 देशों पर किया गया अध्ययन शामिल है। इस अध्ययन के नतीजे भी बहुत व्यापक और गहराई लिए हुए हैं। इनमें 2005 के बाद के तमाम आंकड़ों को शामिल किया गया है। यहां हम भारत को केंद्र में रखते हुए इस रिपोर्ट के नतीजों के बारे में बातचीत करेंगे। पाठकों को भी प्रसन्नता या खुशहाली की अवधारणा को लेकर वैसा ही रोष हो सकता है जैसा कि मुझे हुआ। परंतु मुझे कुछ ऐसी साहित्यिक सामग्री मिल गई जिसकी मदद से मैं उस सामग्री तक पहुंच सका, जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। मुझे उस चर्चा के बारे में कभी और बात करनी चाहिए और यहां खुद को कुछ ऐसे संकेतकों तक सीमित रखना चाहिए जो गुणात्मक हैं।

व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के नमूनों की बात करें तो उन्हें हर वर्ष, हर देश में दर्ज किया गया और लोगों से कहा गया कि वे खुशहाली का आकलन 1 से 10 के मानक पर करें। उसके बाद विभिन्न देशों के प्रदर्शन में जो अंतर आया उसे छह चरों के आधार पर सांख्यिकी के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया।

ये छह चर हैं सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, उदारता, प्रतिव्यक्ति जीडीपी और जीवन संभाव्यता। शुरुआती चार चरों का आकलन कुछ सवालों के जवाब हां अथवा न में तलाशते हुए किया गया। ये सवाल कुछ ऐसे थे मसलन: क्या आपके ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर आप याद कर सकें, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आपको अपनी मर्जी का काम करने का अधिकार मिला हुआ है, क्या सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार है और क्या पिछले महीने आपने कुछ धनराशि दान में दी? प्रति व्यक्ति जीडीपी, क्रय शक्ति समता के डॉलर के संदर्भ में है। जीवन संभाव्यता को एक स्वस्थ जीवन की तस्वीर के प्रतिबिंब के बरअक्स रखकर देखा जा सकता है।

जाहिर सी बात है कि केवल इन छह चरों के आधार पर प्रसन्नता या खुशहाली का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता है और इसका संबंध जीवन के अन्य पहलुओं से भी है जो खुशहाली को प्रभावित करते हैं। बहरहाल मैं आकलन प्रक्रिया की बारीकियों में ज्यादा नहीं जाऊंगा। एक सूची में हमने उन चयनित देशों और घटकों को शामिल किया जो प्रसन्नता के क्रम में भारत के लिए मायने रखते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सन 2019 की रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है वह सन 2016-18 के औसत आंकड़ों पर आधारित है। सबसे पहले भारत का परीक्षण करें तो कुल 156 देशों की सूची में भारत का स्थान 140वां है। यानी यह अंतिम कुछ देशों में स्थान रखता है। साफ कहें तो खुशी या प्रसन्नता के पैमाने पर भारत अंतिम 10 फीसदी देशों में स्थान रखता है।

अगर हम इसके घटकों की बात करें तो सामाजिक सहयोग के मोर्चे पर हालत कुछ ज्यादा ही खराब है और कहा जा सकता है कि रिपोर्ट में देश की खस्ता हालत के लिए काफी हद तक यह भी जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंकिंग 50 फीसदी पर है और उदारता के मामले में वह निचले 58 फीसदी देशों में शामिल है।

स्वतंत्रता या आजादी के मामले में यह शीर्ष 27 फीसदी देशों में स्थान रखता है जिसे एक अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी और दीर्घायु के मामले में हमारा देश निचले 25 फीसदी देशों में आता है। दूसरी बात, चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों दक्षिण अफ्रीका और यहां तक कि लैटिन अमेरिका तक की तुलना में भारत में नाखुशी का स्तर बेहद खराब और चिंताजनक है।

नाखुशी के इस पैमाने पर जो देश भारत के आसपास हैं या जो भारत से थोड़ा सा अधिक प्रसन्न या खुश रहने वाले हैं, उनके नाम हैं- जांबिया और टोगो। लाइबेरिया और कोमोरोस थोड़ा और अधिक प्रसन्न रहने वाले देश हैं। अगर हम उस सूची पर नजर डालें जिसमें विभिन्न देशों ने रैंकिंग को लेकर स्वयं अपनी स्थिति की घोषणा की है और अगर उसे संख्यात्मक रूप से प्राप्त सूचकांक पर आंका जाए तो सन 2019 की रिपोर्ट में एक बार फिर भारत दक्षिण एशिया के देशों में सबसे निचले पायदान पर आता है।

इस अध्ययन के लिए भी 2016-18 के औसत आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में 2015-19 की अवधि में खुशहाली सूचकांक में आए अंतर को भी दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया में जिन देशों का प्रदर्शन इस अवधि में सबसे अधिक खराब हुआ उनमें भारत का स्थान सबसे ऊपर है।

आगे और अध्ययन करने से यह भी पता चला कि हाल के वर्षों में भारतीयों की खुशहाली में निरंतर गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में देश की आबादी का एक बड़ा तबका मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुनेगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी नाखुशी को दूर कर पाएंगे?

काम के घंटों को लेकर छिड़ी 888 बनाम 996 की बहस

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

श्रम अधिकार कार्यकर्ता रॉबर्ट ओवेन ने एक श्रमिक की जिंदगी से जुड़ा 888 का चर्चित मुहावरा पेश किया था। इसका मतलब है कि श्रमिक 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे आराम करता है और 8 घंटे वह अन्य कार्यों एवं मनोरंजन में लगाता है। यह एक अतिवादी स्थिति है। ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने गत दिनों एक अलग नजरिया पेश किया। मा ने यह कहकर बड़ा विवाद पैदा कर दिया है कि युवाओं को कामकाजी संस्कृति के 996 मॉडल को एक बड़े वरदान के रूप में देखना चाहिए। इस कामकाजी मॉडल में एक कर्मचारी से हफ्ते में छह दिन तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करने की अपेक्षा की जाती है। मा कहते हैं, 'दुर्भाग्य से कई कंपनियों और बहुत लोगों को 996 मॉडल पर काम करने का मौका ही नहीं मिल पाता है।'

हालांकि ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग इस अवसर का लाभ उठाने में रुचि दिखाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की कोड-शेयरिंग साइट गिटहब पर बने एक चर्चा समूह ने इसे 999.आईसीयू नाम दिया है। यह नामकरण इस ओर इशारा करता है कि हफ्ते में छह दिन 12-12 घंटे काम करने वाले कर्मचारी को आईसीयू में ही जाना पड़ेगा।

वैसे चीन के अलावा कुछ अन्य देशों में भी 996 संस्कृति आम है। मसलन, जापान भी ज्यादा काम से होने वाली मौतों की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या की गवाही न केवल जापान के आंकड़े दे रहे हैं बल्कि जापानी भाषा में इसके लिए एक शब्द 'करोशी' भी है। कर्मचारी या तो काम से उपजे तनाव से जुड़ी बीमारियों से मर रहे हैं या काम के भारी दबाव के चलते अपनी जान दे देते हैं। जापान सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि चार में से एक कंपनी के कर्मचारी महीने भर में 80 घंटे से अधिक काम करते हैं जबकि 10 में से एक जगह पर कर्मचारियों को 100 घंटे से भी अधिक काम करना पड़ता है।

लेकिन मा की सलाह को सबसे ज्यादा गंभीरता से शायद भारत में लिया जा रहा है। जरा इस पर गौर करें: यूबीएस के एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 10 भीड़भाड़ वाले शहरों में भारत के भी दो शहर मुंबई और दिल्ली हैं। सच तो यह है कि दुनिया में सर्वाधिक मेहनतकश लोग मुंबई के हैं। मुंबई के निवासी साल भर में औसतन 3,315 घंटे काम करते हैं। इसकी तुलना में पेइचिंग का एक कर्मचारी साल भर में औसतन 2,096 घंटे काम करता है।

छुट्टियों की संख्या से भी इसका अंदाजा लगता है। ट्रैवल एजेंसी एक्सपीडिया की छुट्टी वंचना रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में भारत के लोग सबसे कम छुट्टियां लेते हैं। भारत वर्ष 2017 में इस सूची में पांचवें स्थान पर था लेकिन पिछले साल वह शीर्ष पर आ गया। इस सर्वे के मुताबिक 68 फीसदी लोगों ने वर्ष 2018 में कामकाज से जुड़ी व्यस्तताओं के चलते या तो छुट्टियों पर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया या फिर गए ही नहीं। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं।

कई शोध बताते हैं कि हफ्ते में 50 घंटे से अधिक काम करने वाले कर्मचारी की उत्पादकता घट जाती है और 55 घंटे से अधिक काम करने पर तो उत्पादकता औंधे मुंह गिरती है। हालत यह हो जाती है कि अगर किसी कामगार से हफ्ते में 70 घंटे काम लिया गया हो तो आखिरी 15 घंटों में उसकी उत्पादकता ना के बराबर होती है। यह सबूत है कि ऑफिस में देर रात तक रहने का यह मतलब नहीं है कि उस कर्मचारी की उत्पादकता भी जरूर बढ़ जाएगी। इससे साथी कर्मचारियों पर दबाव भी बढ़ता है। हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू की रिपोर्ट में कहा गया है, 'कर्मचारी जितनी देर तक काम करते हैं वे निरर्थक होते जा रहे कामों को उतनी ही बेवकूफी से अंजाम देते हैं।'

तकनीक ने तो स्थिति और भी खराब कर दी है। तकनीक के अधिक इस्तेमाल से जुड़े जोखिम व्यक्ति के सोने-जागने की आदतों, अवसाद, बर्नआउट और उसके संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। शुक्र है कि कई कंपनियों को यह लगने लगा है कि इससे किसी को भी लाभ नहीं होता है। यह स्थिति एक कर्मचारी के 'संपर्क में न रहने के अधिकार' को बताती है। जर्मनी में डैमलर अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर रहने के दौरान ई-मेल को ऑटो डिलीट कर देने की सुविधा देती है। इसी तरह फोक्सवैगन ने अपने सर्वर को इस तरह प्रोग्राम किया है कि काम खत्म होने के 30 मिनट बाद कर्मचारी को ई-मेल भेजना बंद हो जाए। अगले दिन उसकी शिफ्ट शुरू होने के आधे घंटे पहले ही फिर उसे मेल भेजा जा सकता है।

लेकिन कंपनियां अपने सबसे काबिल कर्मचारियों पर काम का बोझ लादने की गलती अक्सर करती हैं। ऐसा किया जाना अनुचित है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा वह काम करता है। एक समय के बाद उसे काम बढ़ने का अहसास होने लगेगा और फिर उसे लगेगा कि न केवल काम की तुलना में उसे कम वेतन मिल रहा है बल्कि उसे प्रदर्शन के लिए दंडित भी किया जा रहा है। ऐसे में उस कर्मचारी को सबसे पहले यह महसूस होता है कि उसके काम की गुणवत्ता गिर सकती है।

सोच उस संस्कृति से बचने की है जो अधिक काम को सम्मान से देखती हो। ऐसे माहौल में लोग काम के अजीबोगरीब घंटों को मानक मानने लगते हैं। लेकिन लंबे समय तक देर तक काम नहीं किया जा सकता है। यह सवाल पूछने का वक्त शायद आ गया है: क्या हम स्मार्ट ढंग से काम करने के बजाय केवल कड़ी मेहनत कर रहे हैं?

ऐसी सोच वाले लोगों के बीच रहने का कोई मतलब नहीं है जो यह मानते हों कि बॉस को खुश करने के लिए दिन के 24 घंटे काम करना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन खतरा यह है कि उस सीईओ की टीम में ऐसे लोग रह जाएंगे जो 'जॉम्बी' बन चुके हैं। जहां 888 संस्कृति अब व्यवहार्य नहीं रह गई है वहीं 996 मॉडल भी कारगर नहीं हो सकता है। समाधान तो कुछ और ही है।

कानाफूसी

स्थानीय निकाय बिना राज्य

ऐसी खबरें आ रही हैं कि 15वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और अधिकार देने की अनुशंसा जल्द ही कर सकता है। वित्त आयोग की अनुसंशा के बाद भी इसका लाभ तमिलनाडु को शायद ही मिले क्योंकि यहां कोई स्थानीय निकाय ही नहीं है। पिछले 30 महीनों से यहां पंचायत और शहरी निकाय के लिए चुनाव ही नहीं हुए हैं। इन चुनावों को अक्टूबर 2016 में होना था लेकिन द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम द्वारा चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के चलते मद्रास हाईकोर्ट ने इनपर रोक लगा दी थी। इसके तत्काल बाद राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों के परिसीमन का काम शुरू कर दिया। इस प्रक्रियागत देरी के बाद तमिलनाडु में 200 वार्ड पार्षदों और 12,524 पंचायत नेताओं के बिना ही काम हो रहा है।

निःस्वार्थ काम को सम्मान

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की रैली में स्टेज पर आकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करने वाले युवा को भाजपा ने पुरस्कृत किया। अमित माली नाम के इस युवा को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे और बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने बुधवार को सम्मानित किया। कैमरे के सामने थोड़ा संकोचपूर्वक माली ने सहस्रबुद्धे द्वारा दिया गया फूलों का गुलदस्ता स्वीकार किया। सहस्रबुद्धे ने पार्टी सदस्य न होते हुए भी एक आम नागरिक द्वारा इस तरह के 'नि:स्वार्थ काम' के लिए माली की प्रशंसा की।

आपका पक्ष

विलुप्त होते प्राणियों की मुख्य चिंता

22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया। इस वर्ष का थीम 'अपनी प्रजातियों को बचाएं' था। सरकार और मनुष्य को धरती में मौजूद वन्यजीव को बचाने के लिए कदम उठाना जरूरी हो गया है, क्योंकि जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। इस धरती पर जितना अधिकार मनुष्य का है उतना ही अधिकार जीवों और वन्य प्राणियों का भी है। लेकिन मनुष्य विकास के नाम पर जीवों और वन्य प्राणियों के घर पर अपना आधिपत्य जमा रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलन देखने को मिल रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों का अत्याधिक उपयोग किया जा रहा है। जनसंख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। सरकार ऐसे विलुप्त होने के कगार पर खड़े प्राणियों को बचाने के लिए योजनाएं चला रही हैं। 'प्रोजेक्ट टाइगर' बाघों को बचाने की योजना है लेकिन वन विभाग आज भी इसके शिकार

को नियंत्रण करने में नाकाम रहा है। प्लास्टिक के बेहिसाब प्रयोग के कारण समुद्र में इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे जलीय जीवों के लिए मुसीबत की जड़ बनती जा रही है। मानव क्रियाकलापों के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है। इससे मनुष्य ही नहीं बल्कि जीवों और वनस्पति को भी नुकसान हो रहा है। प्रदूषण

विश्व से विलुप्त होते जीव जंतुओं को बचाने के लिए अभियान की जरूरत है

के कारण नई-नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए दुनिया को एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि जब मनुष्य पृथ्वी के प्रति संवेदनशील होगा तभी कोई समाधान निकल सकेगा। इसके लिए पौधे लगाने का अभियान दुनिया भर में चलाना चाहिए। परिवार नियोजन नीति कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। दुनिया को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का संकल्प लेना चाहिए। वन्य संसाधनों का उपयोग केवल जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। विश्व के औसत तापमान को 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देने के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

चुनाव ड्यूटी में कर्मचारियों की व्यथा

देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव के साथ देश के करीब आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाती है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लाखों जवानों को तैनात किया जाता है। चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाती है तथा राज्य सरकार के अंतर्गत विभाग चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं। एक मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी सहित तीन मतदान अधिकारी तथा बीएलओ होते हैं। सुरक्षा के लिए जवानों की एक टुकड़ी होती है। मतदान से एक दिन पहले या उसी दिन सभी केंद्र पहुंचते हैं। इसके बाद सुबह से मतदान आरंभ होता है जो निर्धारित समय तक चलता है। इस कड़ी में चुनाव दल को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को देखते हुए कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में जाने से कतराते हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में ड्यूटी करने के बाद निर्धारित मानदेय भी सभी को समय पर नहीं मिल पाता है। प्रशासन तथा चुनाव आयोग को मतदान कर्मियों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान देने की जरूरत है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।